चतुर ही नहीं शातिर भी हैं रामदेव

निर्मल रानी

रामदेव ने योग व इसके टी वी प्रचार के माध्यम से पहले तो स्वयं को प्रसिद्धि दिलाई। उसके बाद जब योग के बहाने राष्ट्रीय स्तर पर उनके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी तो नेता उनकी ओर स्वयं आकर्षित होने लगे। क्योंकि स्वभाविक है नेताओं को वह व्यक्ति बहुत भाता है जिसमें भीड़ को आकर्षित करने की क्षमता हो। इसी का लाभ उठाकर रामदेव ने अपने पतञ्जलि परिसर में नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े से बड़े नेताओं मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों को किसी न किसी आयोजन के बहाने आमंत्रित किया।

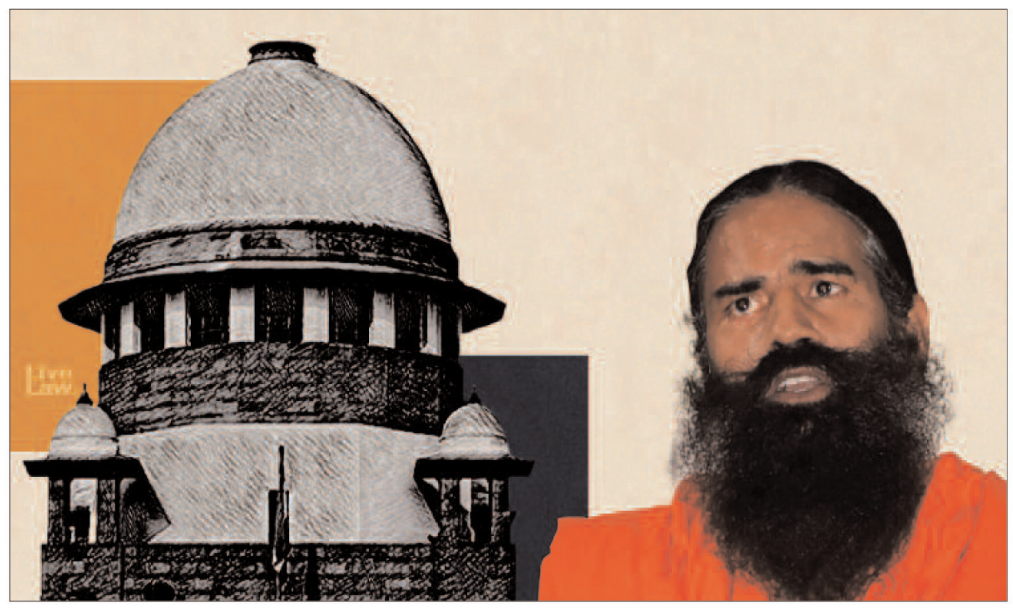

योग गुरु बाबा रामदेव व उनका व्यवसायिक उद्यम पतंजलि आयुर्वेद पिछले दिनों एक बार फिर उस समय सुर्खियों में आया जबकि रामदेव व पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक व सी ई ओ आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले एक दवा विज्ञापन मामले में सर्वोच्च न्यायालय में बिना शर्त अपनी गलती की माफी मांगी।गौरतलब है कि पतंजलि वेलनेस ने एक विज्ञापन देश के टी वी चैनल्स व विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था जिसके माध्यम से एलोपैथी पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसी विज्ञापन को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई में आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में देश के अनेक अखबारों में जारी किए गए गुमराह करने वाले विज्ञापनों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। साथ ही 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के उएड बालकृष्ण व बाबा रामदेव की उस पत्रकार वार्ता के बारे में भी बताया गया जिसमें पतंजलि ने मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करने का आदेश देते हुये यह भी कहा था कि अदालत ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक जुमार्ना लगा सकता है। इसी मामले में अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को 2 अप्रैल को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश भी दिया गया था। परन्तु पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांग ली। अदालत को दिये गये एक हलफनामे में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि उन्हें कंपनी के अपमानजनक वाक्यों वाले विज्ञापन पर खेद है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोर्ट में हाजिर होने के आदेश के बाद पतंजलि आयुर्वेद द्वारा झूठे दावों वाले विज्ञापन के मामले में यह हलफनामा दायर किया गया । इस हलफनामे में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने न सिर्फ बिना शर्त माफी मांगी बल्कि न्यायालय में दी गई अंडरटेकिंग में यह भी कहा कि यह गलती दोबारा नहीं होगी। हलफनामे पर दिये गये इसी माफीनामे में इसतरह के विज्ञापन को पुनः प्रसारित न करने का भी वचन दिया गया है।

योग विद्या को माध्यम बनाकर दिन दूनी रात चौगुनी की दर से अपना व्यवसाय चमकाने वाले रामदेव का विवादों से पुराना नाता रहा है। पतंजलि आयुर्वेद में हालांकि मुख्य चेहरा रामदेव का ही है परन्तु रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद का चेयरमैन व सी ई ओ अपने सबसे विश्वस्त सहयोगी नेपाली मूल के बाल किशन को बनाया है। यही वजह है कि पतंजलि आयुर्वेद में जहां रामदेव का कोई हिस्सा नहीं है वहीं इसके 94 % हिस्से के मालिक अकेले बाल किशन हैं। 51 वर्षीय बालकिशन की गिनती इस समय देश के 68 वें सबसे रईस व्यक्ति के रुप में होती है। उनका नाम फोर्ब्स पत्रिका में अरबपतियों की सूची में भी शामिल है। फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक बाल किशन की अनुमानित नेट वर्थ 3.8 बिलियन डॉलर है। राम देव व बाल किशन ने 2022 में अपना व्यवसायिक टर्न ओवर 40 हजार करोड़ का बताया था साथ ही यह भी कहा था कि उनका लक्ष्य 5 वर्ष में इसे दुगना करने का है।

रामदेव द्वारा आयुर्वेद अथवा इससे सम्बंधित उत्पादों को बनाना बेचना व इनके उचित विज्ञापन देना तक तो ठीक है परन्तु प्रायः वे अपने उत्पाद को सही ठहरने के लिये अक्सर दूसरी औषधीय प्रणालियों पर भी हमलावर हो जाते हैं। उन्हें विश्व विख्यात व सर्व स्वीकार्य एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली से बड़ी चिढ़ है। लोगों का कहना है कि रामदेव अपने उत्पाद बेचने के लिये एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली की आलोचना करते हैं। कोरोना काल में जिस भारतीय वैक्सीन को लेकर भारत सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है उसकी आलोचना में भी रामदेव ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। अभी भी कई जगह सार्वजनिक मंचों से वे यह कहते नजर आते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद तमाम लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यानी एक ओर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी भारत सरकार ने देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने हेतु प्रोत्साहित किया जबकि ठीक इसके विपरीत रामदेव लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रति हतोत्साहित करते रहे। सवाल यह है कि उनमें इतना साहस आता कहाँ से है ?

दरअसल रामदेव ने योग व इसके टी वी प्रचार के माध्यम से पहले तो स्वयं को प्रसिद्धि दिलाई। उसके बाद जब योग के बहाने राष्ट्रीय स्तर पर उनके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी तो नेता उनकी ओर स्वयं आकर्षित होने लगे। क्योंकि स्वभाविक है नेताओं को वह व्यक्ति बहुत भाता है जिसमें भीड़ को आकर्षित करने की क्षमता हो। इसी का लाभ उठाकर रामदेव ने अपने पतञ्जलि परिसर में नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े से बड़े नेताओं मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों को किसी न किसी आयोजन के बहाने आमंत्रित किया। यहाँ तक कि कोरोनकाल में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के हाथों कोरोना की अपनी दवाई कोरोनिल का भी उद्घाटन करा दिया जिसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दवा की विश्वसनीयता को खुली चुनौती दी। रामदेव अनेक मुख्यमंत्रियों व केंद्रीय नेताओं से सम्बन्ध बनाकर विभिन्न राज्यों में अपने उद्योग के विस्तार हेतु जमीनें भी ले चुके हैं। वह रामदेव ही थे जिन्होंने पहले तो 2012 में ट्वीट किया कि अगर कालाधन वापस आ गया तो पेट्रोल 30 रुपये प्रति लीटर मिलेगा परन्तु जब तेल की कीमतें 100 रुपए से ऊपर चली गयीं तो बड़ी ही चतुराई से उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर कर डाला। बाबा रामदेव 2014 से पहले लोगों से पूछा करते थे कि 'आप लोगों को कौन सी सरकार चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार या 300 रुपए वाली सरकार? नरेंद्र मोदी की सरकार बनाओ, 40-45 रुपए लीटर पेट्रोल और 30-35 रुपए लीटर डीजल मिलेगा। यही नहीं गैस की कीमत भी 400 रुपए कर देंगे। रामदेव 20 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा भी करते फिरते थे। इसी सम्बन्ध में करनाल में जब एक पत्रकार ने रामदेव से पेट्रोल की कीमतों संबंधी उनके पुराने बयान के बारे में पूछा तो रामदेव उसपर आग बबूला हो गए। रामदेव ने पहले तो उसे चुप हो जाने को कहा। फिर कहा कि -हाँ मैंने कहा था। क्या पूंछ उखाड़ लेगा मेरी ? तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने का कोई ठेका ले रखा है मैंने? कर ले क्या कर लेगा। चुप हो जा। आगे कुछ पूछेगा तो ठीक नहीं।' इसी तरह कुछ समय पूर्व बाबा रामदेव ने ओबीसी समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुये कहा कि मेरा मूल गोत्र है ब्राह्मण गोत्र, और मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं। ओबीसी वाले ऐसी तैसी करायें। परन्तु जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो बाबा रामदेव साफ मुकर गये और कहा कि मैंने कभी ओबीसी पर कोई बयान नहीं दिया बल्कि मैंने तो ओवैसी कहा था क्योंकि उनके पूर्वज हमेशा राष्ट्रविरोधी रहे हैं। अपनी ही कही बात से साफ मुकरने और इसतरह घुमाने की कला कम ही लोगों को आती है। कहना गलत नहीं होगा कि बाबा रामदेव केवल चतुर ही नहीं बल्कि शातिर भी हैं।

(यह लेखिका के अपने विचार हैं)

संपादकीय

जरूरी है युद्ध विराम

रमजान के महीने में भी गाजा में नरसंहार जारी है। इस अमानवीय घटनाक्रम से चिंतित होकर अंततः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च को एक प्रस्ताव पारित करके गाजा में युद्ध विराम रोकने की मांग की है। प्रस्ताव में सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई और गाजा के युद्ध क्षेत्र में तत्काल राहत सामग्री भेजने का भी उल्लेख है। सात अक्टूबर, 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद से ही इजराइल बदले की कार्रवाई करते हुए गाजा में हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। इस छह महीनों के दौरान विश्व मंचों से युद्ध विराम की मांग की गई लेकिन यह पहला अवसर है जब सुरक्षा परिषद युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित करने में सफल हो पाई। यह भी इसलिए संभव हो पाया कि अमेरिका मतदान से अनुपस्थित रहा। इससे पहले वह तीन बार युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वीटो लगा चुका था। इजराइल अमेरिका के इस बदलते रुख से स्तब्ध है। उसने अमेरिका पर यह आरोप लगाया है कि उसने अपने सदाबहार मित्र का साथ छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका जाने पर रोक लगा दी है। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका और इजराइल के संबंधों में मतभेद की दीवार खड़ी हो गई है। हालांकि अमेरिका ने अपनी सफाई में कहा है कि हमास को लेकर हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव गैर-बाध्यकारी है। अमेरिका चाहे जो कहे, अब इसका कोई असर इजराइल पर नहीं पड़ने वाला है। वास्तव में अमेरिका फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी युद्ध को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पा रहा है। एक ओर वह हमास को तबाह करने के लिए इजराइल को सैनिक मदद मुहैया करा रहा है, और दूसरी ओर गाजा में हजारों नागरिकों के मारे जाने पर घड़ियाली आसूं भी बहा रहा है। इस समूचे घटनाक्रम का सबसे दुखद पहलू यह है कि हमास और इजराइल दोनों युद्ध विराम को लेकर अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। सुरक्षा परिषद द्वारा पारित युद्ध विराम का यह प्रस्ताव दोनों पक्षों ने खारिज कर दिया है। इजराइल इस प्रस्ताव को विभेदकारी बता रहा है, और हमास को यह भरोसा नहीं है कि इजराइल ईमानदारी से युद्ध विराम को लागू करेगा। इसमें संदेह नहीं है कि गाजा में जारी नरसंहार के कारण इजराइल दुनिया से अगल-थलग पड़ता जा रहा है। इसलिए युद्धरत दोनों पक्षों को अपना अड़ियल रवैया छोड़कर युद्ध विराम के लिए राजी हो जाना चाहिए।

चिंतन-मनन

मृत्यु का अर्थ

मृत्यु एक शात सत्य है। यह अनुभूति प्रत्यक्ष प्रमाणित है, फिर भी इसके संबंध में कोई दर्शन नहीं है। अब तक जितने ऋषि-महर्षि या संत-महंत हुए हैं, उन्होंने जीवन दर्शन की चर्चा की है। जीवन के बारे में ऐसी अनेक दृष्टियां उपलब्ध हैं जिनसे जीवन को सही रूप में समझा जा सकता है और जिया जा सकता है। किंतु मृत्युक को एक अवश्यंभावी घटना मात्र मानकर उपेक्षित कर दिया गया। मृत्यु के पीछ भी कोई दर्शन है, इस रहस्य को अधिक लोग पकड़ ही नहीं पाए। यही कारण है कि जीवन दर्शन की भांति मृत्यु दर्शन जीवन में उपयोगी नहीं बन सका।

जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसने जीवन को जितना महत्व दिया, उतना ही महत्व मृत्यु को दिया। बशत्रे कि वह कलात्मक हो। कलात्मक जीवन जीने वाला व्यक्ति जीवन की सब विसंगतियों के मध्य जीता हुआ भी उसका सार तत्व खींच लेता है। इसी प्रकार मृत्यु की कला समझने वाला व्यक्ति भी मृत्यु से भयभीत न होकर उसे चुनौती देता है। जैन दर्शन में इसका सवार्गीण विवेचन उपलब्ध है।

मृत्यु का अर्थ है- आयुष्य प्राण चुक जाने पर जीव का स्थूल शरीर से वियोग।इसके कई प्रकार हैं। उन सबका संक्षिप्त वर्गीकरण किया जाए तो मृत्यु के दो प्रकार होते हैं- बाल मरण और पंडित मरण. असंयम और असमाधिमय मरण बाल मरण है। अकाल मृत्यु, आत्महत्या, अज्ञान मरण आदि सभी प्रकार के मरण बाल मरण में अंतर्निहित हैं। संयम और समाधिमय मृत्यु पंडित मरण है। जीवन के अंतिम क्षणों में भी संयम और समाधि का स्पर्श हो जाए तो वह मरण पंडित मरण की गणना में आ जाता है। कुछ व्यक्ति मौत के नाम से ही घबराते हैं।

वे जीवन को महत्व देते हैं। अपना-अपना चिंतन है। मुझे इस संबंध में अपने विचार देने हों तो मैं मृत्यु को वरीयता दूंगा। क्योंकि जीवन की सार्थकता भी मृत्यु पर ही निर्भर करती है। किसी व्यक्ति ने तपस्या की है और जागरुकता के साथ धर्म की आराधना की है, तो उसका फल समाधिमय मृत्यु ही है।

सियासत के झटके या झटके की सियासत ?

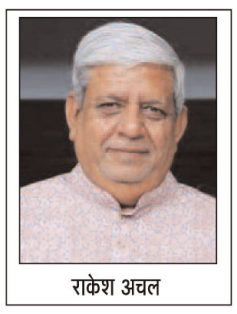

राकेश अचल

फिर हम जैसे रोजाना लिखने वाले लेखकों के लिए मुश्किल ये है कि हमें देश में उनके सामने सियासत के अलावा कुछ भी नया नहीं होता दिखाई देता । नया होता भी होगा तो सियासत का चेहरा इतना बड़ा है कि वो सबको अपने मायामंडल से छिपा लेती है। कल मैंने आपको राजनीतिक दलों की लिस्टों के बाबद बताया था । आज मेरी कोशिश है कि मै आपको सियासत में लगने वाले झटकों या झटके वाली सियासत से रूबरू कराऊँ। मानसिक कसरत आपको भी करना होगी।

चुनावी मौसम में जब लिस्टें बनतीं हैं तब किसी को टिकट मिलता है ,किसी का कटता है। टिकट वितरण की पूरी प्रक्रिया ही झटका आधारित होती है । सियासत का काम ही झटके का दिया जलाकर रखने का है । बात बिहार से करें तो वहां राजद ने बेचारे पप्पू यादव को झटका दे दिय। उनकी पारम्परिक सीट से राजद के पुराने सुप्रीमो लालू यादव की बेटी को टिकट दे दिया गय। बेचारे पप्पू भाजपा से छिटककर राजद के करीब आये थे की बात बन जाये लेकिन नहीं बनी ,उलटे झटका और लग गया।

आपको पता ही है कि भाजपा भी अपने एक युवा तुर्क वरुण गांधी को टिकट न देकर झटका दे चुकी है । वरुण गांधी के बागी होने की आशंका थी लेकिन वे बागी नहीं हुए । खामोशी से अपनी माँ श्रीमती मेनका गांधी का चुनाव प्रचार करने में लग गए । वरुण को जोर का झटका जोर से ही लगा । धीरे से लगता तो और बात थी। लगता है कि भाजपा ने वरुण की राजनीतिक नसबंदी कर दी है। वरुण न खुलकर रो पाए और न अपनी बदनसीबी पर हंस पाए। ऐसे नौजवानों के प्रति मेरी सहानुभूति हमेशा रही है ,भले ही वे किसी भी दल के कार्यकर्ता हों।

सियासत में झटका और हलाल का चलन बहुत पुराना नहीं है। कांग्रेस चाहकर भी झटका राजनीति में दक्षता हासिल नहीं कर पाई है। आम जनता को उम्मीद थी की कांग्रेस अपने बिभीषण केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कोई मजबूत प्रत्याशी देगी,लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया।

समाजवादी पार्टी को भी आजम खान साहब के गढ़ रामपुर से अंतिम मौके पर उम्मीदवार बदलना पडा। जामा मस्जिद के शाही इमाम को ऐन मौके पर प्रत्याशी बनाया गया इसलिए चुनाव चिन्ह तक चार्टेड प्लेन से भेजना पड़ा । सपा के इस फैसले से निवर्तमान सांसद हैं साहब को झटका लगना स्वाभाविक है। लेकिन रामपुर नरेश आजम खान साहब नहीं चाहते थे कि उनकी सल्तनत में पार्टी उनकी मर्जी के खिलाफ किसी को अपना प्रत्याशी बनाये ,कहते हैं कि आजम साहब ठीक उसी तरह से जेल से सियासत कर रहे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली की सल्तनत सम्हाले हुए हैं।

झटके देने में भाजपा दूसरे दलों से सबसे आगे चल रही है । भाजपा की अब तक सात सूचियां आ चुकी हैं और 407 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा की सूचियां हर बार किसी न किसी को झटका देतीं हैं । भाजपा ने जब मंडी सीट से अभिनेत्री कंगना रानौत को अपना प्रत्याशी बनाया तो पता नहीं कितनों को झटका लगा। सियासत में झटका देने की शुरूवात 1985 में कांग्रेस ने की थी । कांग्रेस ने उस दौर में सबसे बड़ा झटका ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे भाजपा के अटल बिहारी बाजपेयी को दिया था । कांग्रस ने ऐन मौके पर पंडित जी के सामने सिंधिया घराने के प्रमुख माधवराव सिंधिया को उतार दिया था। कांग्रेस ने तब आज के शहंशाह अमिताभ बच्चन को भी ठीक उसी तरह मैदान में उतारा था जैसे इस चुनाव में भाजपा कंगना को लेकर आयी है।

झटके देने के तरिके में भी तब्दीली आ रही है । पहले टिकट काटकर या देकर झटके दिए जाते थे,अब पार्टियां स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिलकर या नाम काटकर झटका देतीं है। मिसाल के तौर पर हरियाणा से भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई को पार्टी ने 3 दिन में दूसरा झटका दिया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम गायब है। इस लिस्ट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत एवं राजस्थान से विधायक बाबा बालकनाथ और केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम शामिल है।भाजपा की स्टार प्रचारकों की सूची में मोदी जी के हनुमान अमित शाह का नंबर चौथा है। उनसे ऊपर राजनाथ सिंह ,जेपी नड्डा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद हैं। झटका देने में केंचुआ भी पीछे नहीं है । केंचुआ ने हाल ही में बंगाली नेता सुश्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद दिलीप घोष और कंगना रानौत पर टिप्पणी करने वाली कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस देकर झटकाने की कोशिश की है। केंचुआ ने सबसे पहले यानि चुनावों की घोषणा से भी कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी को भी एक एडवाइजरी जारी कर झटका देने की कोशिश की थी,लेकिन राहुल ठहरे झटकाप्रूफ नेता। दरअसल राहुल गांधी पिछले एक दशक में इतने झटके खा चुके हैं कि उनके ऊपर झटकों का असर होना ही बंद हो गया है । सियासत में ये झटकेबाजी कब तक चलने वाली है ये कोई नहीं जानता। इसलिए आप भी तेल देखिये और तेल की धार देखिये।

मुद्दा : महिलाओं में जागरूकता

कमलेश जैन

पिछले 30-35 वर्षों में जैसे-जैसे स्त्रियों में जागरूकता आई है, नये कानूनों के प्रति वैसे-वैसे उनके अंदर सदियों से दबे-कुचले होने, दोयम दर्जे की नागरिक होने का अहसास गहराया है। पहले वे इसे अपनी नियति मानती थीं, पर अब अधिकार। यह अधिकार खासकर शहरी, शिक्षित स्त्रियों ने समझा है। वे इस अधिकार को अब छीन कर, दूसरे पक्ष को कुचल कर, नेस्तनाबूद करना चाहती हैं। एक हिंसक प्रवृत्ति उनमें जाग गई है। यह घातक है समाज-देश के प्रति। वे जगें अच्छा है, अपना अधिकार भी पाएं पर दूसरे पक्ष को नष्ट करके यह अच्छा नहीं है। इसमें वे खुद भी कहीं की नहीं रहतीं। उनका भी परिवार नष्ट होता है। बच्चे तितर-बितर हो जाते हैं।

एक और बात भी है। वे ऐसा इसलिए करती हैं कि अकेली भी रहें तो तगड़ी एलिमनी या मेंटेनेंस लेकर, बिना काम किए अच्छा जीवन गुजार सकें। इस पूरे काम में उनके माता-पिता, भाई-बहन भी शामिल हो जाते हैं। वे उन्हें लड़ने-झगड़ने, अलग होने, बच्चा लेकर मायके बैठ जाने को प्रेरित करते हैं। ऐसे में उन्हें सास-ससुर, देवर-ननद के लिए कुछ भी करना शुरू से बोझ लगता है। ससुराल जाते ही उनकी रट लग जाती है अलग रहो, मां-बाप को छोड़ो, मेरे घर के पास रहो या वहीं रहो। मेरे मां-बाप की वैसी सेवा करो जैसे अपने मां-बाप की करते हो। वे भी तुम्हारे मां-बाप ही हैं आदि-आदि। आज असंतुष्ट जोड़े लाखों में हैं।

शुरू-शुरू में लड़की ससुराल वालों पर दहेज का, भरण-पोषण के अधिकार का, घरेलू हिंसा का, तलाक का अलग-अलग मुकदमा, चार अलग-अलग राज्यों में करती तो विभिन्न तारीखों पर पति हमेशा इस राज्य से उस राज्य, नौकरी छोड़ भागते रहने को मजबूर हो जाता। माता-पिता को दुखी देखते, 498ए आईपीसी में पूरे परिवार को, नाते-रिश्तेदारों को जेल जाते देख हताशा में वह आत्महत्या भी कर लेता था। पति बचाओ आंदोलन दूर-दूर तक फैलने लगे। वे खुले में अपना ऑफिस भी नहीं चला पाते थे। यह उनके लिए शर्म भरी बात थी कि पत्नी से पीड़ित हैं। ऐसे वकील भी शमार्ते थे, यहां तक कि न्यायालय पूरी तरह से वधुओं के पक्षधर लगते थे।

धीरे-धीरे अदालतों की भी आंखें खुलने लगी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में देखा है कि स्त्रियों ने एक ही केस के 4-5 टुकड़े कर देश के 4-5 भागों में जाकर एक-एक केस करना शुरू किया है। पति चारों तरफ भागता हुआ, अपनी नौकरी, मानसिक शांति खोकर, परिवार को दुखी कर, हताश हो, 15-20 वर्षों में लुटा-पिटा सारी शर्तें मान नष्ट हो जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय कहता है छह वर्ष होते-होते सर्वोच्च न्यायालय आओ और एलिमनी तलाक यहीं पाकर सारे झंझटों से मुक्ति पाओ। पर हैरानी की बात है कि वह ऐसा नहीं कह रहा कि एक ही मुकदमे में सारी बातें एक जगह कह कर सारे झगड़ों से मुक्त हो जाओ।

हाल का सर्वे कहता है-पिछले तीन सालों में देश भर में कार्यरत परिवार अदालतों में सवा तीन लाख से अधिक मुकदमे हुए हैं। यह खुलासा केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़ों से हुआ है। इसकी वजह पति-पत्नी के बीच अहं (इगो) बताया जाता है। हम इसी बात से संतोष किए जा रहे हैं कि विवाद बढ़े तो पर सबसे कम तलाक भारत में होते हैं। देश भर में 812 परिवार अदालत कार्यरत हैं जहां 11 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। परिवार मामलों में विभिन्न तरीकों के केस का अर्थ है-घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, तलाक, बच्चों की कस्टडी, दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, किसी भी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति की घोषणा, वैवाहिक संपत्ति का मामला, गुजारा भत्ता, पति-पत्नी में विवाद पर बच्चों से मिलने का अधिकार, बच्चों का संरक्षक होने का मामला आदि।

बीते तीन वर्षों में दाखिल घरेलू विवाद हैं-2021 में 4,97,447; 2022 में 7,27,587; 2023 में 8,25,502। बीते तीन वर्षों में निपटाए गए विवाद-2021 में 5,31,506; 2022 में 7,44,700 और 2023 में 8,27,000। ऐसा होने का मुख्य कारण है लड़कियों का ऐसे घर में विवाह करना जहां इकलौता लड़का हो, अमीर हो, अच्छी जॉब में हो, माता-पिता वृद्ध हों। ऐसे घर में विवाह करने के बाद लड़की के माता-पिता लड़की को ट्रेनिंग देते हैं-छोटी-छोटी बात पर किच-किच करो, अलग होने की जिद करो, चार-पांच केस करो, जहां जाओ वहां एक केस अलग-अलग राज्य में, हो सके तो एक बच्चा पैदा करो, प्रेग्नेंट होते ही मायके चली आओ, आते ही बच्चे और अपना मासिक भत्ता मांगो, हम साथ हैं। जो लड़की बचपन से मायके में है, उसे वहां का परिवेश जाना-पहचाना लगता है, मोटे माल, संपत्ति की आशा में अब उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है मायके में। पर वह लड़की अपना भविष्य, अपने बच्चे का भविष्य नहीं सोचती। आसान जिंदगी की आशा में एक वीरान जिंदगी उसका आसरा देखती होती है। ऐसे में लड़कियां सोचें, सावधानी से आगे बढ़ें, केस करना है तो आपसी सहमति से तलाक लें, और जल्द अलग हो जाएं।